

सचिव,  
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग

देहरादून, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

विषय: जनपदों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सेल गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2950/XXXVIII/15-30/2013 दिनांक 01 जून, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपद स्तर पर नियोजन, प्रबन्धन, अनुश्रवण तथा प्रशासनिक कार्य हेतु प्रत्येक विभाग डिजिटल सूचना आवश्यकताओं के अनुरूप Geographic Information System; GIS में कार्य किये जाने तथा जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक GIS Cell का गठन किया जाये। जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों में समन्वय करते हुये उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट), उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र तथा एन0आर0डी0एम0एस0 केन्द्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के तकनीकी सहयोग से विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप GIS Cell द्वारा जनपद के Spatial Data Infrastructure का विकास, अद्यतन व अनुप्रयोग (Application) का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा में एन0आर0डी0एम0एस0 के सहयोग से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों, में GIS Cell को स्थापित किया गया था जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एन0आर0डी0एम0एस0 केन्द्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रदत्त तकनीकी सहयोग सम्बन्धी प्रलेख संलग्न हैं।

इसी क्रम में आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1569/XVIII-(2)/17-4(38)/2011 दिनांक 19 जुलाई, 2017 के क्रम में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, अल्मोड़ा में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) लैब के अनुरूप ही समस्त जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) लैब की स्थापना हेतु निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1633/ 66/रा0यो0आ0/2017 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के क्रम में समस्त जनपदों में GIS Cell गठित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त शासनदेशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में GIS Cell गठित किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों यथा: शहरी नियोजन, लैण्डयूज प्लानिंग, वानाग्नि प्रबन्धन, रिसोर्स मैपिंग आदि कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके।

इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या: 2699/XVIII(2)/12-15(29)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, यू-कॉस्ट, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आर0डी0एम0एस0 केन्द्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सविन बंसल)

अपर सचिव